

भारत सरकार  
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2622  
मंगलवार, 19 दिसंबर, 2023/28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

झारखंड में सहकारी समितियां

2622. श्री संजय सेठ:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारी क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों का झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा झारखंड को सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए प्रदान किए गए अनुदान का जिला- वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) झारखंड के जनजातीय बहुल क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों को प्रदान की जाने वाली संभावित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में 7,98,044 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिनकी कुल सदस्य संख्या 29,14,50,241 है। सहकारी समितियों का राज्य-वार आंकड़ा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): सहकारिता मंत्रालय 63,000 कार्यात्मक पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। इस परियोजना के तहत, जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित झारखंड राज्य में कार्यात्मक पैक्स की उपलब्धता के आधार पर, हार्डवेयर, डिजिटलीकरण और समर्थन प्रणाली की खरीद के लिए भारत सरकार के हिस्से के रूप में 10.99 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग के बाद ही आगे धनराशि जारी की जाती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निगम, सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और सहकारी समितियों के विकास के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित झारखंड राज्य को एनसीडीसी द्वारा वितरित ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)			
वित्तीय वर्ष	ऋण	सब्सिडी	कुल
2021-22	0.30	1.49	1.79
2022-23	0.00	4.63	4.63
2023-24 (आज तक)	0.00	0.98	0.98
<b>Total</b>	<b>0.30</b>	<b>7.10</b>	<b>7.40</b>

झारखंड में सहकारी समितियां **अनुबंध- II** में संलग्न विभिन्न योजनाओं के तहत भी एनसीडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-I

क्रम संख्या	नाम	कुल सहकारी समितियाँ (14.12.2023 तक)	कुल सदस्य संख्या
1	झारखंड	11,407	20,92,444
2	जम्मू और कश्मीर	8,615	8,93,319
3	हिमाचल प्रदेश	5,116	18,25,424
4	पंजाब	19,032	34,16,779
5	चंडीगढ़	476	49,721
6	उत्तराखंड	5,289	16,01,219
7	हरियाणा	32,356	54,57,575
8	दिल्ली	5,943	15,69,276
9	राजस्थान	36,827	1,16,43,806
10	उत्तर प्रदेश	43,502	1,84,76,471
11	बिहार	26,640	1,59,98,540
12	सिक्किम	3,789	1,16,098
13	अरुणाचल प्रदेश	1,183	88,761
14	नगालैंड	8,118	3,10,933
15	मणिपुर	10,936	8,19,392
16	मिजोरम	1,229	49,467
17	त्रिपुरा	3,142	5,11,878
18	मेघालय	2,646	2,39,740
19	असम	11,154	43,16,953
20	पश्चिम बंगाल	31,190	95,89,133
21	उड़ीसा	6,780	86,55,612
22	छत्तीसगढ़	8,971	47,50,760
23	मध्य प्रदेश	51,710	1,34,23,189
24	गुजरात	81,023	1,68,31,922
25	महाराष्ट्र	2,22,056	5,80,02,812
26	आंध्र प्रदेश	17,659	95,92,641
27	कर्नाटक	44,526	3,34,45,961
28	गोवा	5,439	15,78,444
29	लक्षद्वीप	35	84,393
30	केरल	6,103	2,73,25,326
31	तमिलनाडु	21,587	2,37,11,414
32	पुदुचेरी	457	4,63,777
33	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,204	1,44,470
34	तेलंगाना	60,107	1,42,98,820
35	लद्दाख	267	27,138
36	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	530	46,633
	<b>कुल</b>	<b>7,98,044</b>	<b>29,14,50,241</b>

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

नोट: केरल और मणिपुर को छोड़कर राज्यों द्वारा 97% डेटा प्रविष्टि पूरी कर ली गई है।

## एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

### I. एनसीडीसी प्रायोजित योजनाएं

**क) युवा सहकार - सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना:** इस योजना का उद्देश्य नए और/या नवीन विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह एनसीडीसी द्वारा बनाए गए सहकारी स्टार्ट-अप और इनोवेशन फंड से जुड़ा है।

**ख) आयुष्मान सहकार:** इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है।

**ग) नंदिनी सहकार:** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता गतिशीलता का समर्थन करना है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं की ब्याज छूट के महत्वपूर्ण इनपुट को एकत्रित करेगा।

**घ) डेयरी सहकार:** यह ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का एक सहकारी डेयरी व्यवसाय केंद्रित ढांचा है। इसमें नई परियोजनाओं के लिए सहकारी समितियों द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और/या विस्तार शामिल है।

**ड) डिजिटल सहकार:** डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, एनसीडीसी ने डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी द्वारा सहायता और क्रेडिट लिंकेज के लिए एक केंद्रित वित्तीय सहायता ढांचे की कल्पना की है, जो भारत सरकार / राज्य / केंद्रशासित प्रदेश से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के साथ मेल खाता है। / सहकारी समितियों के उद्देश्य वाली एजेंसियां डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।

**च) स्वयं शक्ति सहकार योजना:** महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना।

**छ) दीर्घकालिक कृषक पूंजी सहकार योजना:** एनसीडीसी के दायरे में आने वाली गतिविधियों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम देने के लिए एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना।

## II. एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य केंद्रीय योजनाएँ:

क) कृषि अवसंरचना निधि योजना-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

ख) भंडारण और भंडारण बुनियादी ढांचे के अलावा अन्य के लिए कृषि विपणन पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसएएम) की कृषि विपणन बुनियादी ढांचा (एएमआई) उप योजना

ग) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

घ) पीएम मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

ङ) पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) का औपचारिकीकरण - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

च) पीएम '10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन' योजना - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

छ) मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) योजना - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

\*\*\*\*\*